ये मदारियों का लोकतंत्र है, जहाँ प्रधानमंत्री 226 दिन यात्रा करता है

देश के चौकीदार मोदी की यात्रा, प्रचार तंत्र और योजनाओं की घोषणा से जुड़ी रोचक जानकारियाँ...

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

नई दिल्ली- नरेंद्र मोदी से जुड़े पिछले 5 साल के कुछ आंकड़े पेश हैं, जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि देश के फर्जी चौकीदार ने किस तरह देश की चौकीदारी की है।

नरेंद्र मोदी 60 महीने प्रधानमंत्री रहे।

जिसमें 565 दिन यानी 18 महीने 25 दिन विदेश यात्रा पर रहे।

101 दिन यानी 3 महीने 11 दिन पॉलिटिकल यात्राओं पर थे।

यानी 565 दिन में कुल 226 दिन वो केवल यात्रा करते रहे।

15 जून 2014 से 3 दिसम्बर 2018 तक मोदी ने 92 देशों की यात्रा की।

एक देश की यात्रा पर औसतन 22 करोड़ रुपये खर्च हुआ।

92 देशों की यात्रा पर कुल खर्च 20 अरब 12 करोड़ रुपये हुए।

देश में चुनावी रैलियों में मोदी वायुसेना का विमान उपयोग करते हैं। जबकि ये सरकारी यात्रा नहीं होती. इसमें वे वायुसेना के विमान का कमर्शियल रेट (1999 के बाद से रेट रिवाइज नहीं हुए) के हिसाब से मात्र 31000 रुपये भुगतान करते हैं। बताइए देश में इनके आलावा किसे इतने रुपये में चार्टेड प्लेन किराये पर मिलता है?

सत्ता में रहते हुए मोदी सरकार ने 15 मई 2018 तक अलग-अलग योजनाओं के मीडिया में प्रचार-प्रसार पर 43 अरब 43 करोड़ 26 लाख रुपये खर्च किये।

2014-2015

प्रिंट मीडिया ------ 4,24,8500000 (4अरब 24 करोड़ 85 लाख रुपये)

डिजिटल मीडिया ---- 4,48,9700000 (4अरब 48करोड़ 97लाख रुपये)

आउटडोर ऐडवरटाइजिंग ---- 79,7200000 (79करोड़ 72लाख रुपये)

2015-2016

प्रिंट मीडिया ----- 5,10,6900000 (5अरब 10करोड़ 69 लाख रुपये)

डिजिटल मीडिया ----- 5,41,9900000 (5अरब 41करोड़ 99 लाख रुपये)

आउटडोर ऐडवरटाइजिंग ----- 1,18,4300000 (1अरब 18 करोड़ 43लाख रुपये)

2016-2017

प्रिंट मीडिया ---4,63,3800000 (4अरब 63करोड़ 38लाख रुपये)

डिजिटलमीडिया ----- 6,13,7800000 (6अरब 13करोड़ 78 लाख रुपये)

आउटडोर ऐडवरटाइजिंग ----- 1,85,9900000 (1अरब 85 करोड़ 99लाख रुपये)

अभी सरकारी चैनलों के अलावा नमो टीवी और कंटेंट चैनल आ गया है। इसमें सिर्फ मोदी के विज्ञापन चल रहे है। बाकि आपके पास सरकारी चैनलों में DD न्यूज, किसान, मेट्रो, DD इंडिया, DD नेशनल, DD भारती, लोकसभा, राज्यसभा और अरुणप्रभा जैसे चैनल तो हैं ही। देश के हर प्रान्त में हर भाषा के साथ DD का चैनल चलता है.। इनके जरिये सरकार अपने काम बताकर खुद की ब्रांडिंग करती है। इसका बजट 44 अरब 9 करोड़ रुपये सरकार ने तय किया है। इसके आलावा खासतौर पर दूरदर्शन और आल इण्डिया रेडियो के लिए अलग से 28 अरब 20 करोड़ 56 लाख रुपये का बजट रखा गया।

दूरदर्शन और आल इण्डिया रेडियो में DAVP (डॉयरक्ट्रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड विजुअल पब्लिसिटी) और DFP (डॉयरक्ट्रेट ऑफ फिल्म पब्लिसिटी) नामक सरकारी एजेंसियां विज्ञापन बाँटने का कम करती हैं। इन्हें ये विज्ञापन देने के लिए 140 करोड़ रुपये का अलग बजट रखा गया।

मोदी जी इन 60 महीने में 22 महीने सफ़र करते रहे।

यानी वे इन 60 महीने के हर 10वें दिन एक चुनावी रैली करते बरामद हुए।

यानी हर 9वें दिन एक सरकारी योजना का ऐलान करते पाए गए।

जबकि 10 साल की सरकार में मनमोहन सिंह 614 दिन विदेश यात्रा पर रहे और 75 दिन रैलियां की। वहीं मोदी 5 साल में 565 दिन विदेश यात्रा पर रहे और 101 दिन रैलियां करते रहे।

मोदी सरकार ने इन 60 महीनों के दौरान कुल 161 योजनाओं का ऐलान किया। पूरी योजना का जितना बजट नहीं था उससे कई गुना ज्यादा इन योजनाओं के प्रचार पर खर्च कर दिया गया। मोदी ने 50 योजनाओं के प्रचार पर 97 अरब 93 करोड़ 20 लाख रुपये खर्च कर दिया।

जबकि इस देश में रजिस्टर्ड डिग्रीधारी बेरोजगार की संख्या 12 करोड़ है। ये आंकड़े खुद सरकार के हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट रूप से बताया है कि चुनाव के समय जो पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है, उसमें 46 प्रतिशत फंडिंग के बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ से आ रही है और कौन कर रहा है? इस फंडिंग का 90 प्रतिशत पैसा BJP के पास आ रहा है। ये सीधे तौर पर ब्लैकमनी है।

देश में 17 वीं लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव खर्च के ब्योरे कुछ इस प्रकार हैं-

1- 91 सीट (50 हजार करोड़ रुपये खर्च)

2- 97 सीट (80 हजार करोड़ रुपये खर्च)

3- 115 सीट (82 हजार करोड़ रुपये खर्च)

4- 71 सीट (90 हजार करोड़ रुपये खर्च)

5- 51 सीट (2 लाख करोड़ रुपये खर्च)

6- 59 सीट (2 लाख करोड़ रुपये खर्च)

7- 59 सीट (2 लाख करोड़ रुपये खर्च)

यानी चुनाव के दौरान हर सेकेंड 1 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

यानि 5 साल से एक मदारी हमें आंकड़ों के इस मकड़जाल में फंसाकर सत्ता के मजे लूटता रहा। जब भी किसी ने सवाल पूछने की कोशिश की उसे सत्ता की पावर से धराशायी कर दिया गया। हम पिछले 5 साल से एक लोकतंत्र नहीं बल्कि मदारियों के बनाये 'लोकतंत्र' में जी रहे हैं।

स्टिंग ऑपरेशन में सांसदों का खुलासा : पैसे भेजने के लिए हवाला, एंबुलेंस और पुलिस की गाड़ियों का लिया जाता है सहारा

जनचौक ब्यूरो

नये-नये खुले चैनल टीवी9 भारत वर्ष ने स्टिंग ऑपरेशन कर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। कई सांसदों के किए गए इस स्टिंग में ढेर सारी चौंकाने वाली बातें सामने आयी हैं। इसमें भरतपुर से बीजेपी के सांसद बहादुर सिंह कोली का कहना था कि पार्टी ने उनको 50 लाख से ज्यादा रुपये हवाला के जरिये भेजे थे। इसके अलावा पैसों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एंबुलेंस का सहारा लिया जाता है। और कई बार तो पुलिस की गाड़ियां तक इस्तेमाल की जाती हैं।

दिल्ली से बीजेपी के सांसद उदित राज भी इस स्टिंग के घेरे में आ गए। उन्होंने बाकायदा स्टिंग का लाइव प्रसारण देखा और उसी दौरान चैनल के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने लगे। उनका कहना था कि पिछले चुनाव में उन्होंने 5 करोड़ रुपये खर्च किए थे और इस बार 15 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी है। उन्होंने चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की धमकी तक दे डाली।

इसी तरह से बिहार के बाहुबली सांसद पप्पू यादव का भी टीम ने स्टिंग किया है। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि चुनाव में उनके करोड़ों रुपये खर्च हुए।

इसके अलाव इस स्टिंग में सपा के फूलपुर से सांसद नागेंद्र सिंह पटेल और राम विलास पासवान के भाई और सांसद राम चंद्र पासवान भी शामिल हैं। इन सभी ने ढेर सारे खुलासे किए हैं जो जनता के बीच पहली बार सामने आया है।

दिल्ली में बाल्मिकी समाज की एक आवाज, मोदी जैसा झूठा न देखा

दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की पिछले 5 वर्षों में नहीं बढ़ी एक रुपए सैलरी, न हुआ कोई परमानेंट, छह महीने बाद बदलकर—बदलकर रखे जाने वाले सफाई कर्मचारियों की प्रक्रिया भी हुई बंद, लोग मोदी के झूठ वादों के साथ केजरीवाल की वादाखिलाफी से भी हैं नाराज। किस हालत में जी रहे हैं सफाई कर्मचारी, उन्हें पिछले पांच वर्षों में मोदी सरकार से क्या मिला है, केजरीवाल के वादों को वह कितना मानते हैं सही और पहले की कांग्रेस सरकारों को लेकर उनका क्या है रवैया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कैसे हुई है फेल, कैसे सरकारी योजनाएं हो रही हैं दिखावा साबित।

दिल्ली की बाल्मिकी बस्ती में रहने वाली लड़की काजल ने बताया कि कैसे मोदी की बहुप्रचारित कौशल विकास योजना के तहत उसके साथ धोखा हुआ। यह वही समाज है जिसके पैरों को धोकर पानी पीते हैं मोदी, क्योंकि यह समाज पार्टियों और नेताओं की निगाह में भी अछूत है।

समाज के सबसे गरीब और पिछड़े तबके के लोग क्या कहते हैं मोदी सरकार के बीते पांच साल पर, बाल्मिकी समाज के लिए मोदी की योजनाएं कितनी कारगर रहीं और कितनी रहीं जुमला।

- अजय प्रकाश

12 हजार में शौचालय बनता नहीं, और नहीं बनवाने पर राशन रोक देते हैं अधिकारी

अधिकारी पहले सिर्फ 6 हजार देते हैं और कहते हैं कि पूरा शौचालय बना लोगे तो बाकी पेमेंट होगी, पर सवाल यह है कि जिस गरीब के पास भरपेट खाने का अन्न नहीं वह शौचालय का बजट कहां से जुटाए मोदी सरकार की सर्वाधिक महात्वाकांक्षी योजना 'हर घर में शौचालय' की असलियत बताती अजय प्रकाश की रिपोर्ट

जनज्वार, आजमगढ़। मोदी सरकार की सर्वाधिक महात्वाकांक्षी योजनाओं में से एक शौचालय बनाओ अभियान की हकीकत यह है कि पहला पेमेंट अधिकारी केवल 6 हजार की करते हैं और इतने में शौचालय का पूरा ढांचा खड़ा करने के बाद ही 6 हजार देने की बात करते हैं, इसमें भी हजार—दो हजार कमीशन अलग मार लेते हैं।

सरकार का शौचालय हमारे लिए गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि 12 हजार में शौचालय बनता नहीं और नहीं बनवाने पर सरकारों द्वारा गांवों में तैनात अधिकारी जो नहीं बनवा रहे उनका राशन रोक दे रहे हैं। आजमगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके अवधेश यादव आगे बताते हैं, 'यह हाल उस गांव का है जिस गांव को यूपी के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके और मौजूदा सांसद मुलायम सिंह यादव ने गोद लिया है।'

आजमगढ़ के ही पलनी गांव के रहने वाले और यूपी में मानवाधिकारों के लिए सक्रिय रिहाई मंच से जुड़े विनोद कुमार यादव कहते हैं, 'स्वच्छता अभियान की सफलताओं के चाहे जितने गाजे-बाजे विज्ञापनों में बजाए जाते हों, लेकिन हकीकत ग्राउंड पर जाने पर ऐसी सामने आती है कि मुंह से निकल पड़ता है कि मोदी की यह कल्याणकारी योजना है या गरीब ग्रामीणों पर थोपी गयी सरकारी आफत।'

तमौली की रहने वाली गायत्री देवी खुद इन दिनों शौचालय बनवा रही हैं। उन्होंने शौचालय का गड्ढा खुदवा लिया है और

उनका अनुमान है कि कुल 50 हजार लग जाएगा, जबकि उन्हें सरकार की ओर से सिर्फ 6 हजार रुपए मिले हैं। वह बताती हैं कि उन पर शौचालय बनवाने का प्रशासन से दबाव था। शौचालय नहीं बनवाने पर राशन रोक देने की अधिकारी धमकी दे रहे हैं। गायत्री देवी की बात सुन गांव के धर्मेंद्र यादव हंसते हुए कहते हैं, 'मोदी जी की योजना है अगर शौचालय नहीं तो राशन नहीं। इसका मतलब है 'न खाएगा इंडिया न हगेगा इंडिया।'

धर्मेंद्र की बात सुन वहां खड़े सभी लोग हंस पड़ते हैं। लेकिन गांव के ही राजेंद्र सिंह के साथ शौचालय बनवाने वाले अधिकारियों ने जो किया है, उसे लेकर गांव में रोष है। राजेंद्र का भतीजा हमें बताता है कि डेढ़ महीना पहले शौचालय का गड्ढा अधिकारियों ने बलपूर्वक खुदवा दिया। हमारे चाचा नहीं खुदवा रहे थे तो सरकारी अधिकारियों ने 100 नंबर डायल कर पुलिस बुलवा कर खुदवाया। आज डेढ़ महीने बाद भी पैसा नहीं मिला कि चाचा शौचालय बनवा पाएं। उनके पास इतनी कमाई है नहीं कि खुद के पैसे से शौचालय बन सके।

गौरतलब है कि मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को देशभर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और कहा था कि महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ 2 अक्टूबर, 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करना इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

मगर यह स्वच्छ भारत मिशन शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में तो पिछले साल तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार में स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य पूरा करने की हड़बड़ी में आनन-फानन मॉड्यूलर टॉयलेट की मनमाने दामों पर खरीद में करोड़ों के वारे-न्यारे किए गए। भोपाल नगर निगम ने करीब छह करोड़ रुपए की लागत से 1,800 मॉड्यूलर टॉयलेट खरीद का प्रस्ताव रखा था, जिसमें एक ही कंपनी से 12,000 रुपए औसत कीमत वाले टॉयलेट 32,500 रुपए में खरीदे गए।

यही नहीं पिछले साल ही विदिशा में तो स्वच्छता योजना के तहत बनाए गए 1309 शौचालय लापता मिले। दस्तावेजों के मुताबिक 1809 शौचालय बनाए गए, परंतु फिजीकल वेरिफिकेशन में मात्र 500 ही मिले। 1309 शौचालय कहां गए, किसी को नहीं पता।

वेब पोर्टल में शौचालय निर्माण से सम्बंधित जानकारी अपडेट करनी थी। सर्वे दल द्वारा की गई जांच में यह गड़बड़झाला सामने आया।